(b) what is the annual production of ordinary Maruti-800 car;

(c) by what time the waiting list is likely to be cleared at the present rate of production;

(d) whether Government propose to allow some car manufacturers in the private sector to produce cars below 1000 cc in view of the popularity of small cars in the country especially in view of the fact that Maruti Udyog Limited is not in a position to meet the demand of the people; and

(e) if so, what are the details in this regard; and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) All 1983 car booking holders had been offered cars by June, 1987. Of the 1986 bookings, 1,13,864 customers were yet to be offered cars by end of February, 1988.

(b) The production of Maruti-800 standard cars in 1987-88 is anticipated to be about 51,000.

(c) The present waiting list is likely to be exhausted in approximately annother two years.

(d) and (e) The proposals received from four companies in private/State sector to manufacture cars below 1000 cc are under consideration, as a new and comprehensive automobile policy is being evolved by Government.

Incentives to 'no industry districts'

*467. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of all the incentives given to N.I.Ds. (no industry districts), a sizeable number of them in the country have failed to attract even one medium or big industry;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government consider declaring them as a special category of N.I.D. and propose a better package of inncentives so as to give a start to the process of industrialisation of these backward districts?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (c) With effect from 1-4-83, No Industry Distrcts have been included in Category 'A' of re-classified backward areas and made eligible to highest rate of Central Investment subsidy, priority in grant of licences and other concessions.

Out of 93 districts identified as No Industry Districts, Industrial Licences/Registrations have been issued to 61 No Industry Districts for setting up industries there. Normally it takes 3-4 years for a project to fructify and their periods vary from project to project.

There is no proposal for additional special package of incentives to industries.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

*468. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के दौरान उस राज्य में इस प्रकार की और परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

शायद माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश का विवरण जानना चाहते हैं ।

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई और स्थापित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

चालू परियोजनाएं

क्र०स०	उद्यम का नाम	परियोजना का ब्यौरा	अवस्थिति	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5
1.	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	फास्फेट्स	मसूरी	1.20 लाख टन
2.	भारतीय तेल निगम	तेल शोधक कारखाना	मथुरा	60 लाख टन
3.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	खुली औषधियां तथा संरूपण	ऋषिकेश	230 एम०एम० यू० खुली औषधियां
4.	इण्डियन मेडिसन एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपो०	आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी औषधिया	अल्मोड़ा	448 मदें
5.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	संरूपण	लखनऊ	7000 लाख गोलिया आदि
6.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	ताप बिजली सेट	हरिद्वार	—
7.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	संरचनात्मक विनिर्माण	नैनी	26000 टन
8.	भारत इलेक्ट्रोनिक लि०	इलेक्ट्रोनिकी संघटक	गाजियाबाद	—
9.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	पम्पस, कम्प्रेशर्स इत्यादि	नैनी	पम्प 400 नग कम्प्रेशर्स आदि 50 नग
10.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०	फेराइट्स	गाजियाबाद	55.40 करोड़

1	2	3	4	5
11.	इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	एक्सचेंज संघटक	रायबरेली	स्ट्रोजर 50000 नग एवं 1 लाख नग क्रास-बार
		दूरभाष यंत्र	नैनी	2.50 लाख नग
		समाक्ष लाइन उपस्कर	नैनी	30 आर० के० एम०
		ओपन वायर कैरियर सिस्टम	नैनी	1200 चैनल्स
12.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०	इलेक्ट्रानिक्स एवं सहायक कलपुर्जे	कानपुर	—
13.	नेशनल बाइसाइकिल कारपो० आफ इंडिया लि०	बाइसाइकिल	गाजियाबाद	90000 नग
14.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	दुपहिया एवं तिपहिया स्कुटर	लखनऊ	60000 नग 2500 नग
15.	भारतीय आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यूफेक्चरिंग कारपोरेशन लि०	कृतिम अंग	कानपुर	68000 नग
16.	हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि०	वनस्पति तेल	कानपुर	—
17.	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन लि०	जूते आदि	कानपुर	10.01 लाख जोड़े आदि
18.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०	सूत और कपड़ा	कानपुर	—
19.	कानपुर टेक्सटाइल	वस्त्र आदि	कानपुर	—
20.	नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (पू०पी०) लि०	9 मिलें	रायबरेली, कानपुर, सहारनपुर, हाथरस, लखनऊ, नैनी आदि	—
21.	एल्गिन मिल्स कं० लि०	वस्त्र आदि	कानपुर	—

100 करोड़ रु० से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र०सं०	उद्यम का नाम	परियोजना का विवरण	अवस्थिति	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	प्राप्त होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	120 मेगावाट टनकपुर पनबिजली परियोजना	टनकपुर	178.75	मार्च, 90

1	2	3	4	5	6
2.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०	1000 मेगावाट रिहन्द रिहन्द उच्च ताप बिजली परियोजना	रिहन्द	1355.43	जून, 88
3.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०	1400 मेगावाट सिंगरौली सिंगरौली उच्च ताप बिजली परियोजना चरण-II	सिंगरौली	798.77	जनवरी, 88
4.	इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०	स्विचिंग प्रणाली	मानकपुर	211.58	मार्च, 90

(ख) और (ग). नयी योजनाओं जिनके लिये सातवें योजना प्रलेख में विशिष्ट व्यवस्था की गई है :—

क्र० सं०	उद्यम का नाम	सातवीं योजना में प्रावधान (करोड़ रु० में)
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	2.00
2.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि०	8.82
3.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	1.40
4.	एच०एम०टी० लि०	2.00
5.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	2.00

Recommendations of Sudha Joshi Committee

*469. SHRI LAL K. ADVANI:
SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what are the Sudha Joshi Committees recommendations regarding LPG supply and consumer problems indicating the Government's response to each of the recommendations;

(b) what steps have been taken by Government to save the forests which are cut by Adivasis and others for their fuel-needs in the absence of LPG or bio-gas facilities; and

(c) what is the estimated extent of the forests so cut each year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETTROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) The Sudha Joshi Committee has recommended, *inter alia*, review of the existing Marketing Discipline Guidelines keeping in view the complaints received from consumers in order to make them more effective, opening of Emergency Cells and Complaints Cells in all major LPG marketed towns, institutionalised training for mechanics and delivery boys of distributors, and the need for enhancing consumer awareness on the handling and safety aspects of LPG. The recommendations of the Committee which are over one hundred in num-